असंगठित क्षेत्र के संबंध में इकॉनोमिक सेन्सस

2768. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 3

(क) क्या सरकार का असंगठित क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों को अभिलिखित करने वाले "इकोनॉमिक सेन्सस" को प्रकाशित करने का विचार रखती हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) क्या सरकार सन् 1998 के अंत तक इकोनॉमिक सेन्सस का चौथा और पांचवां संस्करण प्रकाशित करने का विचार रखती हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चौथी आर्थिक गणना के परिणामों को दो चरणों में प्रकाशित किया जायेगा । प्रथम चरण में,चयनित महत्वपूर्ण विशिष्टताओं के बारे में त्वरित सारणीय के आधार पर अखिल भारत स्तर पर अनंतिम परिणामों को जारी किया जायेगा । अनंतिम परिणाम, सभी राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों, आन्ध्र प्रदेश को छोड़ कर, जहां पर क्षेत्र कार्य अभी प्रगति पर हैं, प्राप्त हो गए हैं । ये परिणाम जांचाधीन हैं । दूसरे चरण में, विस्तृत परिणाम राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (1987) के चार अंकीय स्तर तक उपलब्ध हो जाएंगे ।

(घ) चौथी आर्थिक गणना के अनंतिम परिणामों को शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा । पांचवीय आर्थिक गणना अभी सूनियोजित नहीं की गई थी ।

Absorption of Employees in Centrally Sponsored Schemes

2769. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

.(a) (he procedure followed for permanent absorption of employees on termination of Centrally sponsored schemes in various States and UTs;

(b) number of such employees retained in the State of Assam since introduction of the Centrally sponsored schemes;

(c) whether the liability are permanently shifted to the State; and

(d) if so, action contemplated to support the States for management of these liabilities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLE-MENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) to (d) Upon termination, Centrally sponsored Schemes (CSS) cease to be the responsibility of the Government of India. It is, therefore, for the State Government concerned to decide the question of absorption, or otherwise, of the employees under the CSS.

As far as the position in Assam is concerned, the information is being collected and will be laid on the table of the House.

India's Position in Infrastructure

2770. SHRI SANATAN BISI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India ranked very low on infrastructure according to a survey done by the National Council of applied Economic Research (NCAER); and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE-IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLE-MENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) NCAER did conduct a Survey of Multi-national Companies regarding Infrastucture and related issues. Their Survey did not involve any ranking of infrastructure in India *vis-a-vis* other countries. The Senior Managers of Multi-National Companies were asked to rate

the various intrastructure related parameters as Very good', 'good', 'fair', 'poor' or 'very poor'. NCAER is yet to finalise its report on the subject.

प्रति व्यक्ति आय

2771. **श्रीमती मालती शर्मा** :

प्रो0 रामबख्श सिंह वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय कितनी रही थी और तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या हैं,

(ख) आर्थिक दृष्टिकोण से प्रति व्यक्ति आय के संबंध में भारत की विश्व में क्या स्थिति हैं, और

(ग) सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा कया हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 1993-94 की सतत् कीमतों और कारक लागत पर प्रति व्यक्ति निबल राष्ट्रीय उत्पाद (एन एन पी) द्वारा मापी गई पिछले तीन वर्षों की प्रति व्यक्ति आय नीचे दी गई है,

क्रं0 सं0	वर्ष	प्रति व्यक्ति एनएनपी
1.	1996-97 (अनन्तिम अनुमान)	9377
2.	1997-98 (त्वरित अनुमान)	9660
3.	1998-99 (अग्रिम अनुमान)	10047

(ख) विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट 1998-99 में भारत को 133 देशों में 92वें स्थान पर रखते हुए 1997 में 6330 डालन के विश्व औसत की तुलना में भारत के लिए 1650 डालर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी एन पी) का अनुमान लगाया हैं जिसे क्रय शक्ति समानता (पी पी पी) के आधार पर मापा गया हैं । अंकित अर्थों के अनुसार मापा गया प्रति व्यक्ति जीएनपी 5130 डालर के विश्व औसत की तुलना में 390 डालर हैं जिससे वह 102वें स्थान पर पहुंच जाता हैं ।

(ग) प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी आय वृद्धि की उच्चतर दर की प्राप्ति और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने पर निर्भर करता हैं । आर्थिक विकास की दर में बढ़ोत्तरी निवेश के स्तर और वर्धमान पूंजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) पर निर्भर करता हैं । जो पूंजीगत प्रयोग की कुशलता की एक माप हैं । विशेषरूप से उन क्षेत्रों में जहां वास्तविक वृद्धि दरें 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष के नौवीं, योजना लक्ष्य से नीचे हैं, वहां निवेश के स्तर को उठाने के लिए तथा निवेश के उपयोग की कुशलता में सुधार लाने के लिए समुचित ध्यान दिया जाता हैं । वार्षिक घातीय जनसंख्या वृद्धि जो पिछले तीन दशकों में 2 प्रतिशत से अधिक थी, अनुमान हैं कि उसमें नौंवीं योजना में प्रति वर्ष 1.62 प्रतिशत तक की गिरावट आएगी ।

Second Launching Pad at Sriharikota

2772. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ISRO is planning to build a second launching pad at Sriharikota;

(b) if so, the details thereof;

(c) when it is likely to be finalised and what will be its likely cost; and

(d) when the second launching pad would be ready?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (d) A project for building Second Launch Pad at SHAR has been approved by the Government in October, 1997 at a cost of Rs. 289.00 crores. The second launched pad will meet the needs of the future launch vehicles besides providing necessary back up to the present launch pad for launching the current generation PSLV and GSLV vehicles. The establishment of the Second Launch Pad is targetted for completion by second half of 2002.